an>

Title: Further discussion on the natural calamities in various parts of the country with special reference to rains and floods in Jammu and Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and drought in Maharashtra raised by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo on the 2nd December, 2014 (Discussion concluded).

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, सिंधिया जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि टेक्निकल मामले में मत जाइए। नौवीं लोक सभा से हम भी यहां पर हैं, यह ध्यान में रहे, बीच में आप भी किसी दूसरे सदन में होंगे, इस सदन में नहीं होंगे। लेकिन जब भी कोई मुख्य विषय होता है, मेहताब जी ने जो बात कहीं, पिछली बार हम सूखा पर चर्चा कर रहे थे, बाढ़ भी उसमें जुड़ गया था, गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, मुझे भी इस बार हस्तक्षेप करना पड़ा और मैंने हस्तक्षेप किया। हमने लगभग 20-25 मिनट तक अपनी बातें रखीं। महाराष्ट्र के सूखे के संबंध में भी हमने कहा। उस समय हमने जो कहा था, उसकी दो लाइनें मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र के सूखे का जो विषय है, उस संबंध में, मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कई राज्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी सूखा है, इसलिए मैं कुछ बातें इसमें रखना चाहता हूं। पूरी चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से दिया जायेगा। संसद के पहले सत्र में हमने चार दिनों तक सूखे पर चर्चा की थी। सामान्यतया सूखा जुलाई-अगस्त के महीने में डिक्लेयर होता है। हम बीच में लोक सभा में नहीं थे, लेकिन जो 25-30 साल से बराबर लोक सभा के सदस्य रहे हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि जुलाई-अगस्त इसका मौसम है। उस समय इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी और उस चर्चा का लाभ भी हुआ था। वह लाभ यह हुआ कि मौसम विभाग जो रिपोर्ट देता है, वह क्षेत्रवाइज, जोनवाइज, डिवीजनवाइज देता है। अब जिलों में क्या स्थिति है, उससे पता नहीं चलता। पिछली बार जब हमने चार दिनों तक चर्चा की, तो उसमें एक बात यह पता चली कि बहुत सारे जिलों और इलाकों में माइनस 50 परसेंट वर्षा हुई। उस समय विदर्भ की स्थिति कुछ अच्छी थी लेकिन मराठवाड़ा की हालत बहुत खराब थी। उसका लाभ यह हुआ कि प्रधान मंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें एक हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी। उसमें चार बिन्दू थे कि डीजल पर राज सहायत दी जायेगी। दूसरा, यदि बागवानी को नुकसान होता है, तो उसे 35 हजार प्रति हैक्टेयर सहायता दी जायेगी। तीसरा, चारा विकास कार्यक्रम के लिए सहायता दी जायेगी। ...(व्यवधान) चौथा बिन्दू यह था कि हम सोयारहित खली, मूंगफली की खली, सूरजमुखी की खली पर आयात शुल्क की माफी की जायेगी। इसका लाभ यह हुआ कि बिहार ने डीजल पर राज सहायता देनी शुरू कर दी। अभी उसका विवरण नहीं आया है। उसके बाद महाराष्ट्र ने कहा कि हमें साढ़े बारह करोड़ रुपये चारे के विकास के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा इतना नुकसान हुआ है। उन्हें सवा छः करोड़ रुपये भेज दिये गये। मध्य प्रदेश ने 16 करोड़ और हरियाणा ने 6.97 करोड़ रुपये का प्रस्ताव चारे के लिए भेजा। बागवानी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 553 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा। इन सबका अध्ययन हो रहा है और यह राशि तुरंत जायेगी। लेकिन सूखे की घोषणा बाद में हुई।

जब हरियाणा में चुनाव शुरू हुआ, तो उसके दो दिन पहले इसकी घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश के बाई-इलैक्शन की घोषणा होने वाली थी, उसके पहले घोषणा हुई। महाराष्ट्र के कई सदस्यों ने यहां बताया कि वहां बहुत पहले से माइनस 50 परसेंट वर्षा हो रही है। ...(व्यवधान) किसी ने डिक्लेयर ही नहीं किया था। लेकिन जब डिक्लेयर किया, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने किया तो वहां हमारी टीम तुरंत गयी। उस टीम की रिपोर्ट भी आ गयी है, जो अब एनडीआरएफ में जायेगी। हम सबको पता है कि एसडीआरएफ का एक फंड होता है, जो राज्यों मे होता है। सूखे की घोषणा राज्य सरकार कर सकती है और उस फंड से खर्चा कर सकती है। उस के बाद यदि वह अधिसूचना जारी कर दे और यहां मेमोरेंडम भेजे तो यहां से टीम वहां जाती है जो आकलन करती है। उसके बाद वह रिपोर्ट एनडीआरएफ में जाती है। महाराष्ट्र में हमने यह स्वीकार किया कि सूखे की घोषणा पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उसमे विलंब हुआ। इस सरकार ने घोषणा की। .(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महाराष्ट्र में इलैक्शन के कारण कोड ऑफ कंडक्ट था। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं बता रहा हूं कि इलैक्शन नोटिफिकेशन के दो दिन पहले हरियाणा ने घोषणा की थी। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले : वहां कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने प्रपोजल भेजा था। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं वही बता रहा हूं कि इसमें इलैक्शन आड़े नहीं आया। ...(व्यवधान) हमारी टीम हरियाणा गयी। ...(व्यवधान) जब सूखे की घोषणा होती है तब राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। ऐसी कोई अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार ने नहीं की, लेकिन हरियाणा सरकार ने की। ...(व्यवधान) आप तो इतिहास बना रहे हैं कि इन्टरवीन करने के बाद दोबारा आपके आग्रह पर मैं बोल रहा हूं। आप पढ़िए, मैंने इतनी सारी बातों का जिक्र किया था। आप बॉयकाट कर गए थे इसलिए आपके ध्यान में नहीं है। मैं भी अपनी ड्यूटी समझता हूं ताकि यह बात सबके ध्यान में आ जाए। मैं इस नाते तकनीकी विवाद में न पड़कर इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं।...(व्यवधान)

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की, हमने अखबार में खबर देखी। हमने तुरंत खबर ली और दो तारीख की रात को ई-मेल से पेपर को मंगाया। हमारी बात मुख्यमंत्री जी से हुई। कृषि मंत्री जी को मैंने यहां बुलाया। हम जिस दिन जवाब दे रहे थे, उसी दिन हमने सुबह कृषि मंत्री जी को पूरे पेपर्स लेकर बुलाया था चूंकि ई-मेल से भी आए थे लेकिन कुछ और जानकारी चाहिए थी। हमने यहां चर्चा में घोषणा की कि कल हमारी टीम जाएगी। दूसरे दिन हमारी टीम गई। वहां शपथ ग्रहण हो रहा था, उसके बावजूद हमारी टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। राज्य सरकार के अधिकारियों को लेकर जिले में जाना पड़ता है इसलिए 14 से सब जिलों का दौरा बना। उनके अधिकारी बनाकर दे रहे हैं, हमने बनाकर दे दिया है। वहां दो दिन हमारी टीम के लोग रहे।

महाराष्ट्र के इतिहास को आप देखिए। आपको हमने उस दिन भी बताया था कि महाराष्ट्र में 2013-14 में एनडीआरएफ ने 1269 करोड़ की सहायता की थी और वर्ष 2012-13 में 1800 करोड़ रुपए की सहायता की थी। जब आपदा आती है तो इसमें राजनीति नहीं होती है। आपने इतिहास जरूर बनाया कि मंत्री ने जो इन्टरवीन कर दिया फिर उसे बोलना पड़ रहा है लेकिन आपदा की राहत पर राजनीति नहीं होती है। यहां हम और आप राजनीति कर लेते हैं, लेकिन आपदा में न आपकी सरकार ने राजनीति की है और न ही सरकार राजनीति करने जा रही है। आपदा के समय कोई राजनीति नहीं होती है। ...(व्यवधान) मैं यह भी बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एसडीआरएफ में वर्ष 2013-14 में 567 करोड़ रुपया गया था लेकिन वह खर्च नहीं हुआ है। इस बार भी इसकी एलोकेशन 403 करोड़ रुपया है। मैंने वहां के रिलीफ कमिश्नर से बात की, मैं मानता हूं कि खर्च जरूर हुआ होगा लेकिन रिपोर्ट भेजने में आलस्य होता है। हमने वहां के मुख्यमंत्री से रात को कहा है, हो सकता है आज रिपोर्ट आ जाए।...(व्यवधान) आप कुछ समझिए, आप बिना समझे बोल देते हैं।...(व्यवधान) इस साल एसडीआरएफ का 3 करोड़ रुपया पड़ा है, हम इसे जल्दी भेजना चाहते हैं। इसके पीछे हम लगातार लगे हुए हैं। हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तो पूरी सहायता करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाता हूं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am not seeking any clarification or anything but the record should be straight.

Yesterday, Naiduji himself agreed that the Minister of Agriculture will come and he will intervene about Maharashtra drought. According to that, we requested him to reply on the drought. The hon. Minister is telling that we are doing politics on the issue. We are only seeking relief. What relief are you going to give to Maharashtra as also to flood-affected areas like Jammu and Kashmir, Odisha and other places. We are not against anything. You should not say that you had boycotted the House and that you were not present here. Yesterday, it was clarified and according to our request, the Minister himself agreed to reply. Therefore, he should not say that he is doing some great obligation to us. It is his duty to reply whenever this House needs.

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज मुझे ऐसा लगा कि कल जो हाऊस में हुआ, उस पर आदरणीय मंत्री जी कुछ बयान देंगे। महाराष्ट्र के सांसदों ने यहाँ पर जो मुद्दे उठाये, बदकिस्मती से उस पर मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हमने इतना पैसा यहाँ दिया, केवल सैद्धांतिक मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। कल मैंने जो मुद्दे उठाये थे, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने कहा था कि रोज वहाँ पर कम से कम दस से बीस लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि आज तक तकरीबन चार सौ से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, उन आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या वे कदम उठाएंगे?जो पैसा उन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया है, उनको वे वापस करने में असमर्थ हैं। इसलिए रोज़ तकरीबन 15-20 लोग राज्य में आत्महत्या कर रहे हैं। जो फीगर है, वह आज चार सौ से भी ज्यादा हो गयी है। यह चिन्ता की बात है। हम भी इस पर कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों- शिव सेना, भाजपा के लोग बैठे हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा के सभी लोग इसमें शामिल हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इसके संबंध में स्पष्टीकरण दें कि जो कर्जा उन्होंने बैंकों से लिया है, वह ऋण आप माफ करेंगे या नहीं, हम इसका जवाब आप से चाहते हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Sir, I thank you and I appreciate the hon. Minister's intervention where he says that there is no politics in drought. I respect that and I appreciate the packages which the hon. Minister is suggesting for our Government. I think, the whole discussion is centered around humanitarian grounds and not about who is on which side. My only request to you is to take Ashok ji's point ahead. A delegation from Maharashtra met the hon. Minister two weeks ago regarding the milk prices in Maharashtra as well as the drought situation. Specifically if you see what kind of intervention the Government of India is doing to help the basic farmers in the drought situation and the milk growing farmers for whom the prices are rock bottom now. As usual Maharashtra has a wonderful production whether it is cotton, sugarcane or milk.

श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने अभी आत्महत्या की चर्चा की है। कल कौन-कौन से सवाल उठाये गये थे, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कल इंटरवीन किया था और मूल चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय को देना था, उन्होंने विस्तार से इसका उत्तर दिया होगा। ...(व्यवधान) लेकिन अभी जो आत्महत्या का मुद्दा आपने उठाया, उसका उत्तर मैं विस्तार से दे रहा हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में 694 किसानों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की थी। ...(व्यवधान) वर्ष 2008 में कुल 3802 किसानों ने आत्महत्या की थी। राज्य सरकार की रिपोर्ट था कि कृषि कारणों से 694 किसानों ने आत्महत्या की। इसी प्रकार से, वर्ष 2009 में 3141 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 572 किसानों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की थी। यह मैं नहीं बता रहा हूँ, उस समय पता नहीं किसकी सरकार थी। ...(व्यवधान) यदि आप बहुत नहीं सुनना चाहते हैं तो आप एक वर्ष के आंकड़ों के बारे में तो सुन लेंगे। ...(व्यवधान) जैसी आपकी चिन्ता है, वैसी ही मेरी भी चिन्ता है। इसीलिए उस चिन्ता को मैं और मजबूत बना रहा हूँ। इस पर हम दोनों और मजबूती से चिन्ता करें। इसीलिए मैं इतने आंकड़े सदन के सामने रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ ताकि पूरा सदन इस विषय पर गंभीरता से सोचे। वर्ष 2013 में, अभी तक 2013 के आंकड़े आए हैं, वर्ष 2014 के आंकड़े नहीं आए हैं। वर्ष 2012 मे 3786 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 642 लोगों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की की थी। यह जानकारी राज्य सरकार देती है। वर्ष 2013 मे 3145 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 407 लोगों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की की थी। अब चाहे 400 लोगों ने आत्महत्या कृषि कारणों से की हो या बाकी 2700 लोगों ने अन्य कारणों से आत्महत्या की हो, कारण चाहे जो भी हो, पूरी आत्महत्या की चिन्ता करनी चाहिए। कारण अलग-अलग हैं और कृषि के कारणों से 400 एवं अन्य कारणों से 2700 लोगों ने आत्महत्या की। निश्चित रूप से सदन ने आज तक चिन्ता नहीं की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, चिन्ता भी की और यह दौर भी चलता रहा, इसलिए अब हम और आप मिलकर ऐसी चिन्ता करें कि यह दौर रुके और आत्महत्याएं कम हों। इसके लिए हम सभी प्रयास करें, यही मेरी विनती है। आप पूरे दिन इस पर चर्चा कीजिए।...(व्यवधान) हम सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take up item No. 19.

...(*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, हम लोग यह पूछ रहे हैं कि आप क्या कदम उठा रहे हैं?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister has already replied on the issue. If you are not satisfied, then it is a different issue. What can I do for that?

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, they are not going to take any step in this regard. We are not satisfied with the reply of the hon. Minister. So, we are walking out....(*Interruptions*)

16.52 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Rajesh Ranjan and

some otherhon. Members left the House.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Deputy-Speaker Sir, umpteen number of times, this issue was discussed in the House at length.....(*Interruptions*) Sir, you have allowed them and what they have said has gone on record....(*Interruptions*) ऐसा कमेंट नहीं करना। ...(व्यवधान) वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते या दस साल के बाद आएंगे, आपको क्यों चिन्ता हो रही है। मेरा कहना है ...(*Interruptions*)

Sir, an issue was raised and it is a very important issue. Please recall as to when this discussion was admitted, how much time we have spent on it, what was the practice earlier and how many hours we have spent on this issue. The Members who had given notice were not there and they came subsequently. Even then they made a suggestion yesterday that some Members including a former Chief Minister of Maharashtra wanted to make some valuable comments. So, the Government had agreed, the hon. Minister was here and he has responded to them. This reply may not be to their satisfaction. Sir, if they are going to be fully satisfied, then they will not be on that side, they will be joining this side.

My point is, the Government have sent a team. The hon. Minister has given the figures. They quoted some figures about the suicide of farmers. When the Minister started quoting figures of 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012, it is unpalatable to them. When they raise a point, they must be able to hear the other side also as well as the Government's reply. They cannot just say whatever they want, then accuse the Government,

then walk out and then make slogans while walking out. This is not the way to do it.

They have been in power all these years. While they walk out, they may say something as they definitely have the right to say something but at the same time, going on repeating and then saying that they are not allowed to speak is not fair. I hope that they will realize it in future. If there is a debate, let it be a meaningful debate. Let there be a constructive debate. We do not want to politicalise it. In Maharashtra, till yesterday, their Government was there. Today, our Government is there. The Central Government and the State Government must join together and work together to address the problems of the farmers. That is the stand of the Government. There is no question of not taking the views of the hon. Members seriously.